जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424 वर्ष: 19 संख्या: 232 प्रभात जालोर, गुरुवार 28 नवम्बर, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस ई.वी.एम. के मुद्दे पर मोदी सरकार से सीधी भिड़ंत के लिए तैयार

क्योंकि, लगातार हार के बाद ई.वी.एम. पर दोषारोपण ही प्रतिष्ठा बचाने का तरीका बचा है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। कांग्रेस ने अन्ततः ई.वी.एम. के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ दो-दो हाथ करने का निर्णय ले लिया है।

चुनावों में बैलट पेपर के उपयोग को वापस लाने के मुद्दे पर गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को एक मंच पर लाने के लिए एक ठोस समन्वित रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि सभी एक आवाज़ में बोलें।

कांग्रेस के भीतर सभी विरोधी स्वरों को, जो कह रहे थे कि ई.वी.एम. ठीक है, चुप रहने और पार्टी लाइन पर चलने के लिए कहा गया है।

हरियाणा तथा महाराष्ट्र की करारी हार के बाद, ई.वी.एम. पर सारा दोष मढ़ने के अलावा, अपनी लाज रखने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के पास और कुछ नहीं बचा है।

- **कांग्रेस के उन सभी नेताओं से मुंह बंद रखने के लिए कहा गया है जो मानते हैं कि ई.वी.एम. में कोई गड़बड़ नही है, इनमें राहुल गाँधी भी हैं पर उन्हें भी समझा दिया गया है कि ई.वी.एम. पर दोषारोपण जरूरी है।**
- **इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन पहले से ही ई.वी.एम. प्रणाली खत्म करने और बैलट पेपर से चुनाव कराने के हिमायती हैं, और अब इसमें ममता बनर्जी भी साथ आ गई हैं।**
- **29 नवम्बर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ई.वी.एम. व्यवस्था खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किये जाने की संभावना है, इसके बाद यह प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की बैठक में भी पारित किया जाएगा।**

शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन तथा अन्य नेता पहले से ही ई.वी.एम. को हटाने के पक्ष में बोलते रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इन लोगों के साथ सुर मिला रही हैं।

माना जा रहा है कि नवम्बर 29 की सी.डब्ल्यु.सी. (कांग्रेस वर्किंग कमेटी) की बैठक में कांग्रेस, ई.वी.एम. का उपयोग बंद करने की आवश्यकता पर प्रस्ताव पास करेगी और शीघ्र ही इस प्रस्ताव को इण्डिया गठबंधन के सहयोगी दलों की मीटिंग में ले जाएगी, जिसके बाद विपक्ष इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगा। रणनीति तैयार की जा रही है और शीघ्र इसको कार्यान्वित किया जाएगा।

अभी तक कांग्रेस में ई.वी.एम. के समर्थन या विरोध को लेकर कोई स्पष्ट विज़न नहीं था, दो-तीन तरह की बातें हो रही थीं।

सन् 2018 में, राहुल गाँधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस का एक एजेण्डा था, ई.वी.एम. को हटाना, लेकिन, उसके बाद पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर ठंडा पड़ गया और उसे एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

लेकिन माना जा रहा है कि अब, सत्तारुढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच ई.वी.एम. का मुद्दा राजनीति की "सैंटर स्टेज" पर होगा तथा इसकी आवाज़ संसद और उसके बाहर सुनाई देगी।

प्रियंका गांधी आज शपथ लेंगी

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। केरल की वायनाड संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेंगी।

वाड्रा के साथ ही, महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले रवींद्र चौहान भी लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे।

- **प्रियंका गांधी के साथ नांदेड से लोकसभा सदस्य बने रविन्द्र चौहान भी गुरुवार को सदस्यता की शपथ लेंगे।**

इससे पहले, वायनाड के चुनाव अधिकारी ने बुधवार को श्रीमती वाड्रा को वायनाड संसदीय उपचुनाव का निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी उपस्थिति रहे। वाड्रा ने वायनाड के लोगों का जबरदस्त समर्थन कर उन पर विश्वास करने के लिए आभार व्यक्त किया।

कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, आज होगा फैसला

आज हो रही एन.डी.ए. की बैठक में शाह के समक्ष एकनाथ शिंदे, अजित पवार, और फड़नवीस के बीच बातचीत होगी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। गुरुवार को होने वाली नैशनल डैमोक्रैटिक एलांयस (एन.डी.ए.) की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का फैसला होगा।

एकनाथ शिंदे का गुट मुख्यमंत्री के चयन में बिहार मॉडल अपनाने पर जोर दे रहा है। इसलिए बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सम्बंध में कोई निर्णय नहीं हो सका। यह तय हुआ है कि गुरुवार को एन.डी.ए. की बैठक में अमित शाह के सामने महायुति के तीनों नेता एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेन्द्र फड़नवीस बातचीत करेंगे।

मीटिंग में मुख्यमंत्री के पद के अलावा इससे सम्बंधित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी जैसे किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे और किसे मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग जोर-शोर से उठ रही है पर बुधवार को खुद शिंदे ने समझौते के संकेत दिए और कहा कि न तो वे खुद और न ही उनकी पार्टी सरकार गठन में अड़चन पैदा करेगी। शिंदे ने कहा कि उन्हेंने सरकार गठन का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर छोड़ दिया है।

- **शिंदे समर्थक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर शिंदे की पार्टी का कहना है कि बिहार मॉडल की तर्ज पर मुख्यमंत्री का फैसला होना चाहिए।**
- **पर, आज शिंदे ने कुछ नरमी दिखाई और बताया कि उन्होंने प्र.मंत्री मोदी व गृहमंत्री शाह से मिलकर बता दिया है कि न तो वे और न ही उनकी पार्टी महाराष्ट्र सरकार के गठन में कोई अड़ंगा लगाएगी।**

शिंदे ने बुधवार को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के मुद्द पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि "मैंने उन्हें बताया है कि वे जो चाहे निर्णय लें हमारी पार्टी उसे स्वीकार करेगी और जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उसके प्रति कोई असंतोष नहीं रखेगी।"

हालिया विधानसभा चुनावों में महायुति को शानदार जीत मिली है, जिसमें भाजपा को 131, अजित पवार की एन.सी.पी. (नेशनलिस्ट कांग्रेस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष के हंगामे के कारण दूसरे दिन भी नहीं चली संसद

सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। बुधवार को दूसरे दिन भी संसद नहीं चली, क्योंकि विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा किया।

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी स्थगन नोटिस ठुकरा दिए। इनमें संयुक्त संसदीय समिति के गठन, मणिपुर तनाव और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा से सम्बंधित स्थगन प्रस्ताव भी शामिल थे। उन्होंने सबसे पहले राज्यसभा को सुबह आधे घंटे के लिए स्थगित किया और उसके बाद राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्न काल के आरम्भ से ही विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने से लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला काफी क्षुब्ध नज़र आए। सुबह उन्होंने सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बाद में असम के भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने सदन का संचालन किया तथा घोषणा की कि स्पीकर ने सभी स्थगन नोटिस अस्वीकार कर दिए हैं। मंत्रियों व सदस्यों के बयान के बाद, उन्होंने दिन भर के लिए सदन स्थगित कर दिया।

- **लोकसभा स्पीकर विपक्ष के रवैये से काफी क्षुब्ध नज़र आए, लोकसभा में विपक्ष ने सुबह से ही विरोध और हंगामा शुरू कर दिया था।**
- **इसके बाद पहले लोकसभा दोपहर तक फिर पूरा दिन के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर ने विपक्ष के सभी स्थगन नोटिस अस्वीकार कर दिए।**
- **राज्यसभा में भी यही माहौल देखा गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर तनाव, संभल दंगे और जे.जी.सी. की मांग संबंधित विपक्ष के सभी स्थगन नोटिस ठुकरा दिए।**

सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र का आरंभ हुआ तथा उस दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में कोई काम नहीं हुआ। विपक्षी दल गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों पर संसद में चर्चा न कराये जाने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर हिंसा व संभल के दंगे पर भी विपक्ष चर्चा चाहता है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में रोड रोलर तरीकों पर चल रही है और विपक्ष की आवाज दबा रही है।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को भी विपक्ष विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। और जब तक सरकार उन मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं देती, जिन नोटिस जारी किए गए हैं, विपक्ष अपना विरोध जारी रखेगा।

'संविधान दिवस मना रहे हैं, बुजुर्गों का खयाल करें'

जयपुर, 27 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुजुर्ग लोगों को पेंशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि भले ही हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, जिससे उनसे जुड़े पेंशन व अन्य मामलों में उनकी मदद हो सके। जबकि एक कल्याणकारी राज्य में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों के मामलों के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर व पॉलिसी बनाई जाए, ताकि इनकी समय पर मदद हो सके। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह

- **हाईकोर्ट ने कहा, 95 वर्षीय अनपढ़ विधवा के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बायोमैट्रिक नहीं होने के कारण बैंक खाता नहीं खुला व पेंशन नहीं मिली। राज्य सरकार दिशा निर्देश दे, तथा पेंशन दिलाये।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शाह की धमकी का असर, नरम पड़े शिंदे

अन्ततोगत्वा मजबूरी में ही सही पर शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर दावा छोड़ दिया है

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस धमकी के बाद कि अजित पवार की नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भाजपा नेता देवेन्द्र फड़नवीस महाराष्ट्र सरकार का गठन कर लेंगे, शिव सेना नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए अपने दावे को वापस लेने के लिए बाध्य हो गए हैं।

शिंदे ने बुधवार को अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रैंस में जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेकर भाजपा के निर्णय के विरूद्ध नहीं है और वो प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह के निर्णय को मानेंगे। उन्होंने कहा, "मैं सरकार के गठन में बाधा नहीं हूँ तथा एन.डी.ए. (नैशनल डैमोक्रेटिव एलायंस) नेतृत्व का निर्णय मेरी शिव सेना को स्वीकार होगा।"

लेकिन वे गुरुवार को प्रधानमंत्री तथा अमित शाह का अन्तिम निर्देश प्राप्त करने के लिये, फड़नवीस तथा अजित पवार के साथ दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि मोदी और शाह उनके साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को मुम्बई में होना सम्भावित है।

- **शिंदे ने कहा, वे सरकार के गठन में बाधा नहीं हैं, उन्हें भाजपा नेतृत्व का निर्णय स्वीकार होगा।**
- **ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही कहा था कि भाजपा अजित पवार की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। दोनों के पास पूर्ण बहुमत है उन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद शिंदे को अंततः पीछे हटना पड़ा।**
- **भाजपा सूत्रों ने कहा कि देवेन्द्र फड़नवीस के नेतृत्व में बन रही नई सरकार में शिंदे उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। अजित पवार ने पहले ही भाजपा का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है और वे उपमुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं।**

भाजपा सूत्रों ने यहाँ कहा कि एकनाथ शिन्दे अजित पवार के साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में नई सरकार का हिस्सा बनने के लिये सहमत हो गये हैं। शपथ लेने वाले मंत्रिमण्डल में 20 मंत्री होंगे, जिनमें 10 भाजपा से, 6 शिन्दे की शिव सेना से तथा 4 अजित पवार की एन.सी.पी. (नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी) से होंगे।

प्रिंसिपल व दो शिक्षकों ने नाबालिग से गैंगरेप किया

मनेंद्रगढ़ , 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में एक स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षकों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की मदद करने के आरोप, वन विभाग के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, आरोपियों की पहचान सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रावेन्द्र सिंह कुशवाह के रूप में हुई है। अशोक कुमार कुशवाह और कुशल सिंह परिहार दोनों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। बनवारी सिंह वन विभाग का कर्मचारी है।

लड़की के साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया। पहली घटना 15 नवंबर को हुई, जब लड़की को एक आरोपी के घर ले जाया गया और हेडमास्टर और दो शिक्षकों ने कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी। दूसरी

- **छत्तीसगढ़ में आरोपी प्रिंसिपल व शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।**
- **आरोपी पढ़ाई में मार्गदर्शन देने के बहाने छात्रा को एक आरोपी के घर ले गये और गैंगरेप किया।**

घटना 22 नवंबर की है। जब पीड़िता किराने का सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर जा रही थी, तो आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर उसे बस स्टॉप के पास रोका और धमकी दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वह उसे अपनी बाइक पर वन विभाग के कर्मचारी के किराए के आवास पर ले गया, जहां फिर से उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।

दूसरी घटना के बाद, लड़की ने अपने माता-पिता को बताया, जिन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पढ़ाई में मार्गदर्शन देने के बहाने लड़की के करीब आया, जो दूसरे स्कूल में पढ़ ती थी। पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चारों आरोपियों पर बी.एन.एस. धारा 70(2) (नाबालिग से सामूहिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झांसी कॉलेज अग्निकांड में तीन निलम्बित

लखनऊ, 27 नवंबर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में नवजात बच्चों की मौत के मामले में हुई जांच के बाद कालेज के प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है जबकि कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को चार्जशीट दी गई एवं तीन अन्य को निलंबित किया गया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को बताया कि अग्निकांड को लेकर गठित चार सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को यह कार्रवाई की गयी है।

- **चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने कार्यवाही की।**

उन्होंने बताया कि इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह के नेतृत्व में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर दावा कर रही हैं ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने साफ कहा, तृणमूल रबर स्टम्प नहीं है जो कांग्रेस की हर बात माने

-डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। पश्चिमी बंगाल में हाल ही में हुये विधान सभा चुनावों में हाल में हुई विजय से उत्साहित एवं प्रफुल्लित, टी.एम.सी. प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी दलों में अपनी श्रेष्ठता पर जोर देते हुये, राजनैतिक रूप से अपना सीना ठोक रही हैं ताकि इंडिया ब्लॉक उनके नियंत्रण में आ जाये।

हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई जबरदस्त पराजयों के बाद, इंडिया ब्लॉक में एक दरार के संकेत देते हुये, तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि टी.एम.सी. इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के निर्णयों के लिये रबर-स्टाम्प नहीं बनेगी। कथित भ्रष्टाचार पर संसद में चर्चा पर कांग्रेस के जोर के साथ मतभेद व्यक्त करते हुये, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि पार्टी चाहती है कि संसद में काम-काज हो, जिससे पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के मुद्दों को संसद में उठा सके।

तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) के सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के रूख को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बनर्जी ने जोर देते हुये कहा है कि टी.एम.सी. और कांग्रेस दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सदस्य हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टी.एम.सी. की चुनावी सहयोगी पार्टी नहीं है तथा टी.एम.सी. कांग्रेस द्वारा लिये गये "इकतरफा निर्णयों" को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है।

कांग्रेस और टी.एम.सी. ने लोकसभा चुनाव तथा हाल ही में हुये पश्चिम बंगाल के उपचुनाव अलग-अलग लड़े थे। टी.एम.सी. ने उपचुनाव की सभी छः सीटें जीत लीं हैं तथा

- **तृणमूल नेताओं ने कहा, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है पर प. बंगाल में कांग्रेस से हमारा गठबंधन नहीं है।**
- **ममता बनर्जी का रूख आज तब और स्पष्ट हो गया जब उन्होंने भ्रष्टाचार पर बहस के कांग्रेस के रूख को ठुकरा दिया और साफ कहा कि उनकी पार्टी सदन चलने के पक्ष में है और विपक्ष के विरोध का हिस्सा नहीं है।**
- **पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी है, इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार करना शुरू कर दिया है।**

लोकसभा चुनावों में भी 40 में से 29 सीटें जीत ली थीं। यह संख्या 2019 के विजेताओं की संख्या से ज्यादा थी, जबकि भाजपा ने राज्य में अपना पूरा जोर लगा दिया था।

एक टी.एम.सी. नेता ने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार, जो विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में से एक है, जिसके कारण संसद के दोनों सदन सोमवार से स्थगित चल रहे हैं, पर चर्चा तो चाहती है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती कि यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की जनता के मुद्दों के महत्व को कम कर दें।

उस नेता ने कहा, "पश्चिम बंगाल को फंड्स से वंचित कर दिया गया है, पूरे देश में कीमतें बढ़ रही हैं तथा हम दुष्कर्म पीड़िताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये कानून लाने पर जोर दे रहे हैं। ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें हम उठाना चाह रहे हैं। इसके लिये, हमारे लिये संसद का चलना जरूरी है।

केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सदस्य होने के बावजूद, टी.एम.सी. और कांग्रेस के बीच का रिश्ता बड़ा असहज है तथा ऐसी भी अटकलें हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले, यह क्षेत्रीय दल विपक्षी गठबंधन से अलग हो जाये। हालांकि ममता बनर्जी तथा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शामिल हैं, के बयानों द्वारा दोनों दलों के बीच की दरारों को ढ़कने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन वे बार-बार दिखाई देने लगती हैं।

अक्टूबर में, हरियाणा में हुई कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के प्रमुख दल कांग्रेस पर प्रहार करने में बहुत तत्परता दिखाई तथा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस को "अहंकार" हो गया है तथा वह उन राज्यों, जहाँ वह स्वयं को मजबूत मानती है, में क्षेत्रीय दलों के साथ समायोजन नहीं करती है।

तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने कहा था, "इस प्रवृत्ति से चुनावों में नुकसान उठाना पड़ता है- 'अगर हम यह महसूस करते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो हम क्षेत्रीय पार्टी के साथ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)